



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 गोल्फ खेलें और रनों की संख्या बढ़ाए : युवी की अनोखी सलाह

6 भाषाई अमदता के चरम पर भारतीय राजनीति

7 नहीं सोचा था कि मैं भावशून्य चेहरे से भी हंसा सकता हूं : मनोज बाजपेयी

फर्स्ट टेक

मोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज वाराणसी (उप्र)/भाषा। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक पवन सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी के कैंट थाने के प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि अदालत के आदेश पर बुधवार को यह मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी के व्यवसायी विशाल सिंह के वकील आशीष सिंह ने बताया कि साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉस' में निवेश के नाम पर उनके मुर्दाकिल के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में विशाल की मुलाकात मुंबई में फिल्म निर्देशक प्रेम शंकर राय से हुई थी, जिसके बाद फिल्म बनाने के सिलसिले में उनकी कई लोगों से मुलाकात हुई। वकील ने बताया कि इस दौरान विशाल से फिल्म के निर्माण में निवेश करने का आग्रह किया गया और बदले में मुनाफे में हिस्सा देने का वादा किया गया।

अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 2,205 की मौत हुई : तालिबान जलालाबाद/एपी। अफगानिस्तान में पिछले सप्ताह आए भूकंप में तबाह हुए घरों से सैकड़ों शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2,200 से अधिक हो गई है। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रविवार रात आए 6.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कई प्रांतों को हिला दिया, जिससे भारी तबाही हुई। भूकंप से कई गांव तबाह हो गए और लोग मिट्टी, कच्ची ईंटों और लकड़ी से बने मकानों के मलबे में दब गए, जो इस झटके को सहन नहीं कर पाए। ज्यादातर जान-माल की हानि कुनार में हुई है, जहां लोग ऊंचे पहाड़ों से घिरी नदी की घाटियों में रहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने बताया कि बचाव और खोज अभियान जारी है।

जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल की किंगस्टन (जमैका)/एपी। भ्रष्टाचार, असमानता और आर्थिक समस्याओं से त्रस्त जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने बृहस्पतिवार तड़के एक कड़े मुकाबले के बाद तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल की। प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि होलनेस की जमैका लेबर पार्टी ने कम से कम 34 सीट जीती हैं, जबकि मार्क गोल्डिंग की विपक्षी पीपुल्स नेशनल पार्टी ने कम से कम 29 सीट पर जीत हासिल की है। गोल्डिंग ने एक संक्षिप्त भाषण में चुनावी हार स्वीकार करते हुए कहा कि वह नतीजों से निराश है।

05-09-2025 | 06-09-2025
सूर्योदय 6:17 बजे | सूर्यास्त 5:57 बजे

BSE 80,718.01 (+150.30)
NSE 24,734.30 (+19.25)

सोना 10,637 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम
चांदी 131,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

मगवान में भेद

हम तो अब तक पढ़ते आए, ईश्वर अल्लाह एक समान। सर्व पूज्य हैं सभी देवगण, राम कृष्ण गौतम हनुमान। भिन्न भले हो धर्म जातियां, हैं अभिन्न सबके भगवान। मत के मतभेदों में लड़झा, बांट रहा इनको ईसान।।

जीएसटी 2.0 देश की वृद्धि के लिए खुराक, अब नहीं थमेंगे अगली पीढ़ी के सुधार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जीएसटी व्यवस्था में किए गए व्यापक सुधारों (जीएसटी 2.0) को राष्ट्र के लिए समर्थन और वृद्धि की 'दोहरी खुराक' करार देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की शृंखला अब नहीं थमेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से यह वादा किया था कि दिवाली और छठ पूजा से पहले देशवासियों को 'डबल धमाका' मिलेगा। उन्होंने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था अब अधिक सरल हो गई है और नई कर दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी जीएसटी परिषद की



बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब को चार से घटाकर दो स्लैब पर लाने और दैनिक उपभोग वाली अधिकांश वस्तुओं को पांच प्रतिशत के स्लैब में लाने के फैसले के एक दिन बाद आई है। जीएसटी परिषद ने अब सिर्फ पांच एवं 18 प्रतिशत की दो कर दरें ही रखने का फैसला किया है जबकि विलासिता एवं अहितकर उत्पादों को 40 प्रतिशत के विशेष कर दायरे में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के दौर में आम घर-परिवार और खेती-

गेमिंग बुरी नहीं, जुआ बुरा है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गेमिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन जुआ खेलना बुरी चीज है और युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग बाजार पर हावी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बाजार में रोजगार के बड़े अवसर हैं। उन्होंने कहा, अगर सही तरीके से काम किया जाए तो भारत वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग बाजार पर अपना दबदबा बना सकता है, इसमें रोजगार के भी बड़े अवसर हैं। गेमिंग बुरी चीज नहीं है, लेकिन जुआ बुरा है। हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए।

उद्योग उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जीएसटी सुधारों का लाभ : गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को बृहस्पतिवार को "परिवर्तनकारी" एवं आजादी के बाद का "सबसे बड़ा सुधार" करार दिया और उद्योग जगत से इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों से करीब सभी क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी और देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। उन्होंने उद्योग जगत से 'भेद इन इंडिया' को बड़े पैमाने पर



बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। गोयल ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी में कमी से हर उपभोक्ता को लाभ होगा। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्ष में की गई कई पहल के फलस्वरूप कल जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों में जो सुधार किया गया...वह

परिवर्तनकारी है। इसका दवा क्षेत्र पर तथा किसानों से लेकर हमारे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) तक विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। गोयल ने कहा, देश के प्रत्येक हितधारक, प्रत्येक उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को "बड़ा बदलाव" बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह कदम 2047 तक विस्तारित देश बनने की यात्रा में आने वाले महीनों व वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोयल ने उद्योग जगत से "जीएसटी के सभी लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने" का आग्रह किया।

दौरा



केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को पंजाब के अमृतसर जिले के बाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रभावित किसानों से बातचीत की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय से कहा

अगर न्यायाधीश शुल्क को वैध नहीं मानते तो अमेरिका 'आर्थिक तबाही के कगार' पर होगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वॉशिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय से शुल्क पर त्वरित और निर्णायक निर्णय का अनुरोध किया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों और सहयोगियों पर उनके द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के बिना देश आर्थिक तबाही के कगार पर होगा।

ट्रंप प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों में जिस तरह आर्थिक तबाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे बेहद



असामान्य हैं। बुधवार देर रात, उसने न्यायाधीशों से अपीली अदालत के उस फैसले में हस्तक्षेप करने और उसे पलटने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप के ज्यादातर शुल्क आपातकालीन शक्तियों वाले कानून का अवैध इस्तेमाल हैं। फिलहाल, ये शुल्क लागू रहेंगे।

शुल्क और उनके अनियमित क्रियान्वयन ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया है, अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों और सहयोगियों को अलग-थलग कर दिया है, तथा ऊंची कीमतों और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। राष्ट्रपति ने शुल्क का इस्तेमाल यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों पर नए समझौते स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए भी किया है। अगरत के अंत तक शुल्क से राजस्व कुल 159 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी समय की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है।

डीआरडीओ ने तीन आधुनिक सामग्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किया

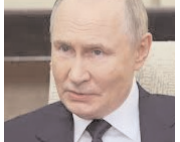
नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने उद्योग भागीदारों को तीन उन्नत पदार्थ प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी. कामत ने हाल में एक कार्यक्रम में उद्योग भागीदारों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंसिंग समझौते (एलएटीओटी) के दस्तावेज सौंपे। मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल) ने उद्योग भागीदारों को तीन उन्नत सामग्री प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं। डीआरडीओ के सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को और अजबूत करते हुए, ब्यूरो की गतिविधियों में सहयोग के लिए प्रयोगशाला के अनुभव, सुविधाओं और क्षमताओं का उपयोग करने हेतु डीएमआरएल और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत, चीन जैसे देशों पर उपनिवेशवादी दबाव की नीति अपनाने पर पुतिन ने ट्रंप की निंदा की

ट्रंप में समझ की कमी : पुतिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बीर्लिंग/भाषा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन जैसी "सशक्त अर्थव्यवस्थाओं" के खिलाफ उपनिवेशवादी नीति अपनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है। पुतिन ने यह भी कहा है कि साझेदार देशों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। चीन की विजय परेड में भाग लेने यहां



पहुंचे पुतिन ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और चीन जैसे भारी जनसंख्या वाले शक्तिशाली देशों की अपनी घरेलू राजनीतिक प्रणाली और कानून हैं। पुतिन ने कहा, जब कोई आपसे कहता है कि वह आपको सजा देगा, तो आपको यह सोचना चाहिए कि इन बड़े देशों के नेता, जिनका इतिहास भी कठिन दौरों से गुजरा है, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि इन देशों को लंबे समय तक उपनिवेशवादियों और उनकी

संप्रभुता पर हमलों का सामना करना पड़ा है। पुतिन ने कहा, आपको यह समझना चाहिए कि अगर इनमें से कोई एक भी कमजोरी दिखाता है, तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है और यही बात उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, उपनिवेश युग समाप्त हो चुका है। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे अपने साझेदारों से बातचीत में अब ट्रंप की निंदा की है। पुतिन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनमें इन देशों और उनके नेताओं के बारे में समझ की कमी है।

गौरतलब है कि ट्रंप ने भारत को निशाना बनाते हुए रूस से तेल खरीदने पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरुआत में चीन पर 145 प्रतिशत शुल्क लगाया, लेकिन बाद में उसे कम करके एक अंतरिम समझौता किया, जिसके तहत चीनी सामानों पर शुल्क 145 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि अमेरिकी सामानों पर चीन का शुल्क 125 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।

भारत और सिंगापुर ने वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने की प्रतिबद्धता जताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत और सिंगापुर ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनके सिंगापुरी समकक्ष लॉरेस वोंग की मौजूदगी में अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के लिए एक रोडमैप का अनावरण किया, जिसमें दुनिया में मौजूदा भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। अपनी यात्रा के दौरान मोदी और वोंग ने उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, हरित नौवहन, कोशल विकास, असेन्य परमाणु ऊर्जा, विमान और रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें मानवसहित जहाजों के विकास में संभावित सहयोग भी शामिल है। दोनों पक्षों ने पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो विमान, कोशल विकास, हरित और डिजिटल नौवहन, अंतरिक्ष और डिजिटल



दोनों पक्षों ने पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो विमान, कोशल विकास, हरित और डिजिटल नौवहन, अंतरिक्ष और डिजिटल परिसंपत्ति नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेंगे

परिसंपत्ति नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेंगे, जिसमें अगली पीढ़ी के वित्तीय बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। वोंग एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को तीन दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के रूप में यह भारत की उनकी पहली यात्रा है। सिंगापुर के साथ भारत के संबंधों

को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह देश भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। हरित नौवहन पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) से हरित और डिजिटल शिपिंग कोरिडोर (जीडीएससी) की स्थापना पर सहयोग में सुविधा होगी।

भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया, एशिया कप फाइनल के करीब पहुंचा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

राजगीर (बिहार)/भाषा। भारत ने बृहस्पतिवार को यहां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण के अपने दूसरे मैच में मलेशिया को 4-1 से हरा दिया।

भारतीय टीम ने धीमी शुरुआत की जबकि शफीक हसन ने दूसरे ही मिनट में मलेशिया को बढ़त दिला दी लेकिन मेजबान टीम ने शानदार वापसी की। मनप्रीत सिंह (17वें मिनट), सुखजीत सिंह (19वें मिनट), शिलानंद लाकड़ा (24वें मिनट) और विक्रम सागर प्रसाद (38वें मिनट) ने भारत के लिए गोल किए। भारत ने बुधवार को अपने पहले सुपर 4 मैच में कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला था। इस जीत से भारत दो मैच में चार अंक के साथ सुपर 4 तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। वह चीन और मलेशिया से आगे है जिनके तीन-तीन अंक हैं जबकि गत चैंपियन कोरिया केवल एक अंक के



साथ अंतिम स्थान पर है। शुक्रवार को विमान के बाद भारत शनिवार को सुपर 4 के अपने अंतिम मैच में चीन से भिड़ेगा जबकि मलेशिया का सामना कोरिया से होगा। रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए भारत को चीन के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ की आवश्यकता है। मलेशिया बृहस्पतिवार को अपने दो मुख्य खिलाड़ियों के बिना खेला। पिछले मैच में चीनी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर हुई झड़प के बाद अनुशासनहीनता के

कारण फिटरि सारी को मैच के लिए निलंबित कर दिया गया था। अबू कमाल अजराई भी भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। भारत को दूसरे ही मिनट में झटका लगा जब मलेशिया ने हसन के गोल से बढ़त बना ली। मलेशियाई खिलाड़ी हसन ने संजय और जुगराज सिंह को चक्का देकर अपनी रिवर्स स्ट्रिक से गेंद को गोल में पहुंचा दिया। पहले क्वार्टर में भारतीय रक्षा पंक्ति थोड़ी कमजोर दिखी लेकिन उसने कोई और गोल नहीं खया।

शुरुआती हमले को छोड़कर भारत ने पहले क्वार्टर में गेंद पर कब्जा और मौकों के मामले में दबदबा बनाए रखा। भारत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और दूसरे क्वार्टर के शुरुआती मिनट में लगातार पांच पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए जिनमें से आखिरी को मनप्रीत ने गोल में बदला। मनप्रीत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के प्लिक को हाफिजुद्दीन ओथमान द्वारा बचाए जाने के बाद रिबाउंड से गोल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने फिर जोरदार हमले किए और दो मिनट बाद उनके प्रयास रंग लाए। सुखजीत ने नजदीक से गोल दामा। इस बढ़त के बाद भारतीय खिलाड़ी अलान नजर आए और उन्होंने मलेशियाई गोल पर लगातार हमले करते रहे। भारत ने जल्द ही शिलानंद के जरिए स्कोर 3-1 कर दिया। हार्दिक सिंह ने दिलीप्रीत सिंह को पास दिया और शिलानंद ने मलेशियाई गोलकीपर के पास से इसे डिफेंड कर दिया।

‘समाज में नकारात्मकता के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट प्रयास की आवश्यकता’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर। शहर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान केलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी व सोशल साइंस के संस्थापक डॉ अच्युत सामंत द्वारा प्रारंभ किए गए ‘इंडिया अगेस्ट नेगेटिविटी’ (आईएएन) अभियान का 11वां स्थापना दिवस गत दिनों भुवनेश्वर के एक होटल में मनाया गया जिसमें देश के विभिन्न शहरों ने जाने माने वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष फगन सिंह कुलरस्ते उपस्थित थे। संस्थापक डॉ अच्युत सामंत ने सभी



का स्वागत किया तथा कहा कि भारत से नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम सभी को एक साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज में नकारात्मकता बढ़ने से पहले ही उसे रोका जाना चाहिए। इससे समाज को कोई लाभ नहीं होगा, इसके लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

सांसद फगन सिंह कुलरस्ते ने स्थापना कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि आईएएन के 11वें स्थापना दिवस समारोह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को हमारे समाज में व्याप्त नकारात्मकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने भारत परिवेश में

नकारात्मकता को बहुत खतरनाक बताते हुए देश में सकारात्मक वातावरण को बढ़ाना है। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित ऑर्गनाइजर के प्रधान संपादक प्रफुल्ल केतकर ने कहा कि सबसे बड़ी नकारात्मकता मातृभाषा में बोलने, बात करने व संवाद करने में झिझक है। हमारी

शिक्षा प्रणाली अभी तक औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं आई है। जब हम अपने संस्थानों को भूल जाते हैं तो नकारात्मकता फैलती है। उन्होंने कहा, नकारात्मकता के विरुद्ध भारत को अपने दायरे से आगे बढ़कर सकारात्मकता के लिए भारत बनना होगा। उन्होंने कहा कि

नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना शुरू करना होगा। वर्चुअल रूप से बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कर्नाटक के सेवानिवृत्त लोकयुक्त तथा आईएएन सलाहकार बोर्ड के सदस्य एन संतोष हेगड़े ने कहा कि डॉ. सामंत द्वारा शुरू की गई इस नकारात्मकता के विरुद्ध भारत पहल का एक विशाल आयाम है। सामंत, जो आदिवासी लोगों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं, ने उन्हें सकारात्मकता फैलाने वाली बताया। भारत में रखांडा की उदाहरण जैकलीन मुंकेगीरा ने कहा कि हमें महात्मा गांधी से अहिंसा विरासत में मिली है। अहिंसा मानवीय गरिमा की रक्षा का एक अच्छा तरीका है।

जीएसटी विभाग नए कर ढांचे के सुचारु क्रियान्वयन के लिए उद्योग से कर रहा समन्वय: सीबीआईसी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय अग्रयक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जीएसटी विभाग 22 सितंबर से लागू होने वाले नए कर ढांचे को सुचारु ढंग से लागू करने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर उन्नत बनाने पर काम कर रहा है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि उद्योगों को उन वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जमा होने को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, जिन पर कर की दरों में कटौती की गई है। वे इस संचित आईटीसी का इस्तेमाल कर के भुगतान में कर सकेंगे। जीएसटी परिषद ने बुधवार को आम सहमति से माल एवं सेवा कर में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी। परिषद ने पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, लक्जरी और अहितकर वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय किया गया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। अग्रवाल ने साक्षात्कार में कहा, बहुत कम समय के लिए संचित दरों में कई बदलाव हुए हैं। 40 प्रतिशत की एक नई दर लागू की

गई है। हमें विश्वास है कि हमारे पास उपलब्ध करीब दो सप्ताह के समय में हम नए शुल्कों और नई शुरूआत के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी विभाग ने पहले ही उद्योग जगत से संपर्क कर लिया है और उन्हें सूचित कर दिया है ताकि वे भी अपनी जीएसटी संबंधी प्रणालियों को उन्नत कर सकें। अग्रवाल ने कहा, वे (उद्योग जगत) इन बदलावों को अपने एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणालियों में भी शामिल कर सकते हैं, ताकि शुरूआत सुचारु रूप से हो और इसमें कोई गड़बड़ी न हो। हमें इस बात का पूरा भरोसा है। फॉर आईटीसी से जुड़ी उद्योग की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर अग्रवाल ने कहा कि ऐसी वस्तुओं के वितरक इनपुट (कबे माल) पर करों का भुगतान उचित भी दर पर करते हैं, उस पर पूरा आईटीसी प्राप्त करने के हकदार होंगे। अग्रवाल ने कहा, जब वे 22 सितंबर से सामान बेचेंगे या आपूर्ति करेंगे, तो नई दरें लागू होंगी। तब वे आईटीसी का उपयोग कर सकेंगे। यह उन्हें रिटर्न दाखिल करते समय शुल्क भुगतान के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि आईटीसी शायद बहुत कम समय के लिए संचित होगा और उसके बाद यह फिर से सुचारु हो जाएगा।



ई-रिक्शा के लिए भी भारत-एनकैप जैसा सुरक्षा मानक लाने पर विचार: गडकरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार देश में सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा के लिए भी ‘भारत एनकैप’ की तर्ज पर सुरक्षा मानक लाने पर विचार कर रही है।

गडकरी ने फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार एवं संगोष्ठी के सातवें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा, देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। इनमें से 66.4 प्रतिशत मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले लोगों की होती हैं। उन्होंने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया। गडकरी ने इस प्रयास में ई-रिक्शा को सुरक्षित बनाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, ई-रिक्शा की संख्या देश में बहुत अधिक है। हम देख रहे हैं कि किस तरह इनके लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया जा सकता है। हम ई-रिक्शा के लिए भी भारत-एनकैप जैसे सुरक्षा मानक लाने जा रहे हैं। उन्होंने चार-पहिया वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के इरादे से वर्ष 2023 में ‘भारत-एनकैप’ सुरक्षा मानक की शुरूआत की थी।

जीएसटी 2.0 भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी शुल्क से निपटने में करेगा मदद: उद्योग जगत

नई दिल्ली/भाषा। जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने का कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि के चक्र को बढ़ावा देने के साथ ही अमेरिकी शुल्क का सामना करने में मदद करेगा। उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने यह बात कही। जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय दर संरचना को बुधवार को मंजूरी दी जो 22 सितंबर से लागू होगी। हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज (इंडिया) के चेयरमैन अशोक पी हिंदुजा ने कहा कि जीएसटी दर में कटौती ने अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर कदम है जो जमीनी स्तर पर मांग को दूर करके भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता का समर्थन करेगा।

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि खपत को बढ़ावा देने और निवेश करने के लिए ऐसे अधिक सुधारों की वकालत की। अधिक और तेजी से सुधार खपत एवं निवेश को उजागर करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। वे बदले में, अर्थव्यवस्था का विस्तार करेंगे और दुनिया में भारत की आवाज को बुलंद करेंगे।

देश में जीएसटी सुधारों से उत्साह, किसी ने कांग्रेस को ऐसा करने से नहीं रोका था: भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को जीएसटी सुधारों को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि इससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा। साथ ही पार्टी ने कांग्रेस के इस दावे पर भी पलटवार किया कि वह करों को युक्तिसंगत बनाने की कोशिश कर रही थी।

भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में किसी ने भी उसे एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू करने से नहीं रोका था। कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा यह उल्लेख किए जाने पर कि उनके नेता राहुल गांधी लंबे समय से जीएसटी परिषद द्वारा घोषित द्वि-स्तरीय कर ढांचे की वकालत कर रहे थे, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजित पात्रा ने कहा कि यह ‘ला ला लेंड’ (स्वन्तलोक) में जी रहे हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है।



पात्रा ने संवाददाताओं से कहा, 2014 से पहले राहुल गांधी और उनकी पार्टी को जीएसटी लागू करने से किसने रोका था? यह उनकी अपनी अक्षमता को दर्शाता है। उन्होंने घरेलू सामान से लेकर कृषि क्षेत्र के उत्पादों और चिकित्सा उत्पादों तक कई वस्तुओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो इन सभी पर प्रस्तावित करों की तुलना में बहुत अधिक वैंट (मूल्य वर्धित कर) लगाया जाता था। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया और उसके पास जटिल कर व्यवस्था को सरल बनाने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का अवसर था, लेकिन उसके पास साहस और इरादे की कमी थी। उन्होंने कहा कि नवरात्र के पहले दिन (22 सितंबर) से जीएसटी की दरों में कटौती से देश में ‘उत्साह’ का माहौल है और इससे सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए पात्रा ने कहा कि उनकी सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों में आम सहमति बनाने की मंशा, साहस और लोकतांत्रिक भावना दिखाई है, जबकि कांग्रेस के लंदन चर्चा और बहस ही कर सकती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह दावा स्वाधीनता के बाद से उसके ‘गरीबी हटाओ’ के नारे जैसा है, लेकिन उसकी सरकारें कभी गरीबी नहीं हटा सकीं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस मानती है कि गांधी

परिवार के कारण ही सूर्य और चंद्रमा उगते हैं और उनके बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं होता। ओडिशा में पुरी के सांसद ने कहा कि जब देश खुशियों से भरा होता है, चाहे वह राम मंदिर निर्माण हो, अनुच्छेद 370 को हटाना हो या अब जीएसटी सुधार, तब शोक मनाना कांग्रेस की मानसिकता है। पात्रा ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की इस आलोचना पर भी निशाना साधा कि बुधवार को सुधारों की घोषणा करने वाली जीएसटी परिषद एक औपचारिकता बनकर रह गई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में ही इन उपायों का सार बता दिया था। भाजपा नेता ने कहा कि मनमोहन सिंह के विपरीत, मोदी एक ‘एक्सीडेंटल’ प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं और यह स्वाभाविक है कि वह अपना दृष्टिकोण सामने रखेंगे जिसे सरकार लागू करेगी।

मराठा आरक्षण जीआर से ओबीसी पर असर नहीं पड़ेगा : फडणवीस

मुंबई/भाषा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद आरक्षण पर उनकी सरकार के कदम से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को किसी भी तरह के अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा।



महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय के सदस्यों को उनकी कुनबी विरासत के ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा के बाद मंगलवार को जरांगे ने यहां आजाद मैदान में अपना पांच दिवसीय अनशन समाप्त कर दिया था। मराठा समुदाय को राज्य में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फडणवीस ने कहा, हैदराबाद गजट के कार्यान्वयन के संबंध में जारी सरकारी प्रस्ताव के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी एवं राकापा के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल से बात की है, जिन्होंने बुधवार को पात्र मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने में तेजी लाने के लिए जारी किए गए जीआर पर खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।

जीएसटी सुधार नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बंपर उपहार : नड्डा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बृहस्पतिवार को जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए इसे दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों को दिया गया ‘‘बंपर उपहार’’ बताया। उन्होंने जीएसटी परिषद द्वारा उठाए गए कदमों में खामियां निकालने के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की और कहा कि यह विपक्षी पार्टी के दोहरे मानदंडों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उन फैसलों का विरोध करते हैं जिनका समर्थन उनकी



पार्टी शासित राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद के सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती संघ सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी लागू नहीं कर पाई क्योंकि राज्यों को उस पर भरोसा नहीं था। उन्होंने दावा किया कि इसके विपरीत, उस समय कांग्रेस ने मूल्य वर्धित कर (वैट) के जरिए गरीबों और व्यापारियों को लूटा और कर

चोरी की भरपूर गुंजाइश छोड़ी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी लागू करके ‘एक राष्ट्र एक कर’ की अवधारणा को साकार किया। जीएसटी परिषद ने बुधवार को जीएसटी में व्यापक सुधारों की घोषणा की, जिसमें 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के कर स्लैब को हटा दिया गया और केवल पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रखे गए। नड्डा ने कहा कि कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है और कई अन्य उत्पादों पर इसे काफी घटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जीएसटी सुधारों की मंशा व्यक्त की थी और अब जीएसटी परिषद ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है।

श्रीनगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों से 200 परिवारों को निकाला गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से करीब 200 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। इस बीच, बृहस्पतिवार को झेलम का जलस्तर घटने से घाटी के अन्य हिस्सों में बाढ़ का खतरा कुछ कम हुआ है। पुलिस के एक प्रवक्ता के अनुसार, जिला पुलिस ने फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया समूहों का गठन किया है। उन्होंने कहा, शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति और भारी जलभराव को देखते हुए श्रीनगर पुलिस ने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और नदी पुलिस के सहयोग से व्यापक निकासी और पुनर्वास योजना शुरू की है, ताकि प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रवक्ता के अनुसार, संबंधित थाना क्षेत्रों की टीम, नदी पुलिस और एसडीआरएफ इकाइयों के साथ मिलकर कई संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई। इन समूहों ने गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों से लगभग 200 परिवारों और व्यक्तियों को निकाला और उन्हें अन्य जगहों पर ले जाया गया। इनमें पीरजो ड्रीप और बसंत बाग से निकाले गए 24 परिवार भी शामिल हैं। प्रवक्ता



ने बताया कि बोनीयारबल, एस.आर. गंज, मलिक साहिब, सफाकदल, पंगोश कॉलोनी, नूरबाग, गुजरबल और मदनयार फतेह कदल से 39 परिवारों को निकाला गया। उन्होंने कहा, करीब 20 परिवारों और व्यक्तियों को देदी कदल, हब्बा कदल, जैनदर मोहल्ला, टंकीपोरा, करन नगर, कुरसू, इकबाल कॉलोनी और अरमवारी से निकाला गया, जबकि 20 परिवारों को टेलबल और हजरतबल के संवेदनशील

इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 63 व्यक्तियों को पंजीनारा-मुजगुंड, बंड साइड, मल्लूरा बंड, ख्वाजा बाग बंड, परिमपोरा बंड, बिलाक कॉलोनी बंड, कमरवारी, रामपोरा छत्ताबल बंड, जेनपोरा और टेंगन से निकाला गया। प्रवक्ता ने बताया कि निकासी प्रयासों के साथ-साथ पुलिस ने तटबंधों में संभावित दरारों की पहचान कर उन्हें बंद किया, जिससे स्थिति बिगड़ने से रोकी जा सकी।

सरकार ने चांदी के गहनों की स्वैच्छिक हॉलमार्किंग शुरू की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक सितंबर से चांदी के गहनों और अन्य वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग शुरू की गई है। इससे उपभोक्ताओं के लिए धातु की शुद्धता सुनिश्चित करने को लेकर एक डिजिटल पहचान प्रणाली लागू की जाएगी।



भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने आईएस 2112:2025 के प्रकाशन के साथ अपने हॉलमार्किंग मानक को संशोधित किया है। यह पहले के आईएस 2112:2014 संस्करण का स्थान लेगा। इस संशोधन के साथ चांदी के आभूषणों और अन्य वस्तुओं के लिए हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी)-आधारित हॉलमार्किंग शुरू की गई है। इससे पता लगाने की क्षमता में वृद्धि हुई है और यह मौजूदा स्वर्ण हॉलमार्किंग प्रणाली के अनुरूप है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, नई प्रणाली के तहत, उपभोक्ता बीआईएस केयर मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके एक सितंबर, 2025 के बाद हॉलमार्क किए गए चांदी के आभूषणों के प्रकार, शुद्धता ग्रेड, हॉलमार्किंग तिथि, परीक्षण केंद्र का विवरण और जौहरी पंजीकरण संख्या की पहचान कर सकते हैं।

संशोधित मानक में सात शुद्धता ग्रेड... 800, 835, 925, 958, 970, 990 और 999... शामिल किए गए हैं। इनमें 958 और 999 ग्रेड नए जोड़े गए हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्र ने बृहस्पतिवार को उद्यमन न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह प्रशिक्षण के दौरान दिव्यांगता के कारण सैन्य संस्थानों से निकाले गए कैडेटों को ‘पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना’ (ईसीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। न्यायमूर्ति बी पी नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शैव्या भारती ने सूचित किया कि 29 अगस्त से ऐसे सभी कैडेटों को ईसीएचएस योजना में शामिल कर लिया गया है। भाटी ने बताया कि उनके लिए एकमुश्त सदस्यता शुल्क भी माफ कर दिया गया है। इस दलील पर गौर करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि पंजीकरण 15 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। इसने साथ ही इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा पल्ली को न्यायमित्र नियुक्त किया। पीठ ने कहा, भारत सरकार के रक्षा

मंत्रालय के सैनिक कल्याण विभाग ने सभी दिव्यांग ‘आउटबोर्ड कैडेटों’ को ईसीएचएस के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता। वर्तमान में अधिकारियों द्वारा देय 1,20,000 रुपये का एकमुश्त सदस्यता शुल्क ऐसे दिव्यांग/आउटबोर्ड कैडेटों से नहीं लिया जाता। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह सराहनीय है। मौद्रिक लाभ के मुद्दे पर, न्यायालय ने 2017 से प्रभावी अनुग्रह राशि पर ध्यान दिया तथा इसे बढ़ाने का आह्वान किया, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए। वर्तमान में लागू बीमा योजना के संबंध में शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं हो सकती। इसने कहा कि ‘आउटबोर्ड कैडेटों’ के प्रयास किए जा सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि पुनर्वास के उद्देश्य से ‘आउटबोर्ड कैडेटों’ का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और केंद्र को चिकित्सा पुनर्मूल्यांकन के लिए योजना तैयार करनी चाहिए।

अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अलवर। राजस्थान में अलवर जिला पुलिस ने उद्योग नगर में अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सैय्यत कॉलोनी, गोलेटा में स्थित 'फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैड' नामक एक हॉस्टल में गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और आवास का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस संस्था का प्रबंधन चेन्नई की एक संस्था एफएमपीबी द्वारा किया जाता है। इसी संस्था से जुड़े गुजरात निवासी सैय्यम, बांधोली निवासी मलकीत सिंह, गोर्बिंदगढ़ निवासी सतीश और बोधर अमृत के साथ 14 अन्य आरोपी पहले ही अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार होकर जमानत पर हैं।

जीएसटी दरों के सरलीकरण से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों के सरलीकरण से आमजन, किसान और व्यापारी को सबसे ज्यादा लाभ होगा तथा अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने जीएसटी परिषद द्वारा दरों का सरलीकरण कर आमजन को राहत देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राजस्थान की आठ करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। शर्मा ने विधायकसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी काउंसिल ने माल एवं सेवा कर सुधारों की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय किया है। अब चार दरों के स्थान पर केवल दो ही

हॉस्टल के रिकॉर्ड और तकनीकी साक्ष्य जब्त किए और बच्चों से सादा वस्त्रों में गोपनीय तरीके से पूछताछ कर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में शामिल दो मुख्य आरोपियों बोधर अमृत (44) निवासी चिटकोड़ा हिम्मतनगर गुजरात और सोहन सिंह (34) निवासी बांधोली थाना रामगढ़ जिला अलवर को गिरफ्तार किया। ये आरोपी गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा और आवास का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस संस्था का प्रबंधन चेन्नई की एक संस्था एफएमपीबी द्वारा किया जाता है। इसी संस्था से जुड़े गुजरात निवासी सैय्यम, बांधोली निवासी मलकीत सिंह, गोर्बिंदगढ़ निवासी सतीश और बोधर अमृत के साथ 14 अन्य आरोपी पहले ही अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार होकर जमानत पर हैं।

दर लागू होंगी।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय रोटी, कपड़ा, मकान जैसे बुनियादी सुविधाओं की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे आमजन, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, उद्योगपति और व्यापारियों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। साथ ही, आने वाली दीपावली भी खास होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अंत्यावय की परिकल्पना को साकार करते हुए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णय देश और राज्यों को विकसित बनाने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य की 'डबल इंजन' सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है।



मुख्यमंत्री के निर्देश पर फील्ड में उतरे अधिकारी

जयपुर। जयपुर जिले में विगत दिनों हुई लगातार बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और वर्षाजलित परिस्थितियों के दौरान प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने की मंशा को मूर्त रूप देते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में नगर निगम जयपुर हैरिटेज, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जयपुर विकास प्राधिकरण, नागरिक सुरक्षा और एसडीआरएफ जैसी सभी इकाइयों को समन्वित कर प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की और मिशन मोड में प्रभावितों तक राहत पहुंचाने का काम किया है। जिला प्रशासन द्वारा वर्षाजलित परिस्थितियों से निपटने के लिए

युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। बीते तीन दिनों में जयपुर में हुई भारी बारिश के दौरान नगर निगम जयपुर हैरिटेज को बाढ़ नियंत्रण केंद्रों और कार्यालयों पर कुल 330 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से सभी का त्वरित निस्तारण किया गया। जलभराव एवं भिंड़ी कचरा रोकने हेतु 19,800 मिट्टी के कटों का उपयोग किया गया, 15 पंप लगाए गए, जबकि जवाहर नगर कबी बस्ती में तीन अतिरिक्त पंप स्थापित किए गए। साथ ही 3, 100 फीट सड़क मरम्मत और 180 नालों व मैनहोल पर कवर लगाए गए। विद्युत संबंधी 450 शिकायतों में से 280 का निस्तारण तत्काल किया गया। राहत कार्यों में 7 जेसीबी, 13 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 4 डंपर अतिरिक्त लगाए गए।



सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के ध्येय से करें कार्य : दीया कुमारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में तथा महिला एवं बाल विकास शासन सचिव श्री महेन्द्र सोनी एवं निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं श्री वासुदेव मालावत की उपस्थिति में गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं जर्जर / मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी भवनों के जीर्णोद्धार के कार्यों की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि उक्त कार्य समयबद्धता से पूर्ण करें तथा आवंटित किए गए बजट का समुचित उपयोग किया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के ध्येय से अधिकारी फील्ड में कार्य करें साथ ही नियमित मॉनिटरिंग भी करें। उसाह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित रूप से तय लक्ष्यों की प्राप्ति

के जिला उपनिदेशक यह भी सुनिश्चित करें कि जिलों में असुरक्षित और जर्जर आंगनबाड़ी भवनों को डेमोलिश किया जाए तथा उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए इसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। दीया कुमारी ने अभी तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाने वाले जिला उपनिदेशकों से नाराजगी जताते हुए कहा कि जिलों से अगले 15 दिवस में प्रगति की चर्चा की जाएगी।

सिविल कार्य हुए हैं या नहीं इसकी प्रगति रिपोर्ट अगले एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि आंकड़ों में कोई अंतर नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमित रूप से तय लक्ष्यों की प्राप्ति



राज्यपाल ने किया मीडिया लैब एवं रेडियो राजस्थान 91.2 कन्सुनिटी रेडियो का लोकार्पण

जयपुर। पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में गुरुवार को दीक्षास्थ समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने की। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय की नवनिर्मित मीडिया लैब एवं रेडियो राजस्थान 91.2 कन्सुनिटी रेडियो का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन नई शिक्षा नए विचार और विकसित भारत का संकल्प की थीम पर किया गया।

राज्यपाल श्री बागडे ने नव आंगतुक विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अहंकार का त्याग कर अर्जुन की तरह एकाग्रता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह नीति प्राचीन गुरुकुल परंपरा की तरह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। उन्होंने एकालम मानवतावाद के महत्व को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को इच्छा शक्ति और संयम के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

राज्यपाल ने राजस्थान को वीर प्रसूताओं की भूमि बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में अर्जुन लाल सेठी जैसे शिक्षकों के योगदान को याद किया।



रबी सीजन में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता : पंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय स्थित समिति कक्ष में राज्य स्तरीय फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि रबी सीजन उर्वरक-प्रधान होता है, इसलिए सभी फर्टिलाइजर कंपनियों मांग और आपूर्ति का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष अप्रत्याशित वर्षा के कारण किसानों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कृषि आयुक्त को निर्देश दिए कि नियमित मॉनिटरिंग कर किसी भी समस्या का प्राथमिकता से तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाकर कालाबाजारी रोकने, सहकारी समितियों से पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का सख्ती से पालन कराने

के निर्देश दिए।

उन्होंने रेलवे विभाग को निर्देश दिए कि मांग के समय दबाव कम करने के लिए जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और दोसा रेल पॉइंट्स को विकसित कर नई सुविधाओं से मजबूत किया जाए। वर्तमान में राज्य में 35 रेल रोक पॉइंट्स कार्यरत हैं, जिनमें से 15 पर नियमित, 12 पर मौसमी और 8 पर आकस्मिक आपूर्ति होती है।

बैठक में कृषि एवं उद्योगिकी आयुक्त सुचिन्मयी गोपाल ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उर्वरक संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारी प्रस्तुत की। प्रस्तुति में बताया गया कि इस वर्ष अब तक राज्य की खरीफ सीजन मांग में से यूरिया की आपूर्ति 98 प्रतिशत रही, वहीं डीएपी की उपलब्धता 88 प्रतिशत तक पहुंची। एनपीके और एमओपी की स्थिति अपेक्षाकृत कम रही। जिला-वार समीक्षा में अधिकांश जिलों में यूरिया और डीएपी की अधिकतम उपलब्धता दर्ज की गई।

बैठक के दौरान कंपनीवार समीक्षा में पाया गया कि यूरिया की आपूर्ति में जीएसएफसी ने 224 प्रतिशत आपूर्ति कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, आईपीएल ने 153 प्रतिशत

लक्ष्य पूरा किया, जबकि आरसीएफ की आपूर्ति सबसे कम (लगभग 69 प्रतिशत) रही। डीएपी के मोर्चे पर कोरोमंडल ने लक्ष्य से अधिक आपूर्ति दर्ज की। साथ ही किसानों ने डीएपी पर निर्भरता कम करते हुए वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया, जिसमें एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) का उपयोग 28 प्रतिशत और एनपीके का 83 प्रतिशत अधिक दर्ज किया गया।

बैठक में विभागीय प्रयासों की जानकारी दी गई। जिलास्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर आपूर्ति की निगरानी की जा रही है और सभी दुकानों पर स्टॉक व मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। नियम उल्लंघन पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक अधिक विक्रय करने वाले 981 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था), सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सहित विभिन्न विभाग- कृषि, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रेलवे तथा उर्वरक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चट्टान गिरने से तीन युवकों की मौत, एक घायल

अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ उपखंड के नौगांवा थाना क्षेत्र में गुरुवार को पहाड़ से गिरी चट्टान की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गयी, जबकि एक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रघुनाथगढ़ पंचायत के काला घाटा की सरकारी पहाड़ी की ओर गांव के शकील (25), भब्ल (30), जुबेर (25) और जाहिद पहाड़ी पर बकरियां चरा रहे थे। तेज धूप से बचने के लिए चारों एक पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि अचानक 25 फुट की ऊंचाई से भारी चट्टान मलबे के साथ उनके ऊपर आ गिरी। इससे चारों मलबे में दब गये। उनकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जेसीबी मंगाकर मलबा हटाया। चारों को मलबे से निकाला गया, लेकिन तब तक शकील, भब्ल और जुबेर की मौत हो चुकी थी, जबकि जाहिद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नौगांवा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अलवर भेज दिया गया। उधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार शर्मा और उपखंड अधिकारीअनिल मीणा पुलिस जाते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस ने शव नौगांवा अस्पताल के शवगृह में रखवाये हैं।

डोडा पोस्ट की तस्करी करने के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के दोषी को गुरुवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त फारुख उर्फ कालू कायमखानी को मादक पदार्थ डोडा पोस्ट की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार 25 मई 2016 को गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फारुख से 305 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया था।

वर्ष 2016 में कही बात सरकार ने मानी : गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर जो बात वर्ष 2016 में कही थी, अतः नौ साल तक जनता को महंगाई का झटका देने के बाद अब मोदी सरकार ने मान ली। गहलोत ने गुरुवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इतना विलंब क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि अब इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाहवाही लूटना चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी के सुझाव को पहले ही मानकर इस फैसले को पहले ही ले लेते तो आमजन और अर्थव्यवस्था का इतना नुकसान न होता।

राजस्थान के अनेक भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी

जयपुर। मौसम विभाग का मानना है कि राजस्थान के अनेक हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का दौर अभी कुछ दिन जारी रहने की संभावना है। उसने बृहस्पतिवार को भी राज्य में अनेक जगह अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। विभाग ने बृहस्पतिवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सतलुबर एवं उदयपुर जिलों में अति भारी बारिश का 'अरेंज अलर्ट' जारी किया है। इसके अलावा भी सिरोही, नागौर, पाली एवं टोंक समेत दर्जन भर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक आगामी तीन-चार दिन राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभागों के कुछ भागों में मध्यम से भारी एवं कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभागों के कुछ भागों में माध्यम से कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोरपुर, बीकानेर संभागों के कुछ भागों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। जोधपुर संभाग में पांच से सात सितंबर तक कहीं-कहीं भारी एवं अतिभारी बारिश होगी। बृहस्पतिवार सुबह तक 24 घंटों में राज्य के दोसा, उदयपुर, बूंदी एवं बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश तथा राज्य के अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश सिकराय (दोसा) में 104 मिलीमीटर हुई।

आईआईटी जोधपुर के निदेशक पर हमले के आरोप में सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर के एक सहायक प्रोफेसर को विभागीय बैठक के दौरान संस्थान के निदेशक के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। शिक्षक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि, बाद में शाम को आईआईटी (कानून एवं व्यवस्था), सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सहित विभिन्न विभाग- कृषि, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रेलवे तथा उर्वरक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रोफेसर दीपक कुमार अरोड़ा के खिलाफ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और जातिभेदक अपराध कहने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि अरोड़ा ने निदेशक अग्रवाल पर हमला किया, जिससे उनके पैर में चोट आई है। दूसरी ओर, अरोड़ा ने भी निदेशक और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें उन पर गलत तरीके से बंधक बनाने, सरकारी कर्तव्यों में बाधा डालने और मारपीट का आरोप लगाया गया। सूत्रों के अनुसार, जब निदेशक कार्यालय के कर्मचारियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो अरोड़ा ने एक कर्मचारी के साथ भी मारपीट की, जिससे उसके हाथ में चोट आई। अरोड़ा ने निदेशक को कथित तौर पर जातिभेदक अपराध कहे और उन्हें और उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। सूत्रों ने बताया कि अरोड़ा उस समय भड़क गए जब निदेशक ने पिछले पांच वर्षों में उनके विभाग के खराब प्रदर्शन की शिकायत की। हालांकि, अरोड़ा ने उनका विरोध करते हुए कहा कि संस्थान के निदेशक के रूप में उनके कार्यभार संचालन के बाद से आईआईटी ने भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है।

राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां पर टिप्पणी को लेकर आक्रोश

जोधपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वर्गीय मां पर की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात में आक्रोश का माहौल है। इसी के चलते शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद राहुल गांधी की शव यात्रा निकालकर उनका पुतला चलाया गया। भाजपा जोधपुर देहात दक्षिण के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की माता पर टिप्पणी करना बेहद अनुचित है। राजनीति में व्यक्तिगत स्तर पर माता-पिता पर की गई बातें सही नहीं मानी जा सकतीं।

नवनिर्मित श्रीपरशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन 6 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। ब्राह्मण समाज के युवाओं के शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन के स्वप्न को साकार करने वाला एक भव्य केन्द्र अब जयपुर की धरती पर खड़ा हो चुका है। विप्र फाउंडेशन की ओर से नवनिर्मित श्रीपरशुराम ज्ञानपीठ (सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च) का उद्घाटन 6 सितम्बर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इस अवसर पर नीरजा मोदी स्कूल ग्राउंड में दोपहर 3 बजे ब्राह्मणों का महासंगम होगा जिससे मुख्यमंत्री सहित प्रमुख वक्ता संबोधित करेंगे। इससे पूर्व 2 बजे से गौ ऋषि प्रकाशदास जी महाराज राष्ट्र भक्ति ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति देंगे।विप्र फाउंडेशन के संस्थापक

संयोजक सुशील ओझा ने बताया कि एक लंबे अरसे के बाद समाज के बालक-बालिकाओं को एक ही छत के नीचे शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कौशल विकास, कन्या छात्रावास, ई-लाइब्रेरी और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी तमाम सुविधाएं मिलने जा रही हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च समाज के युवाओं के संपूर्ण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

ओझा ने बताया कि ज्ञानपीठ के उद्घाटन को लेकर समाज में अभूतपूर्व उत्साह है। उद्घाटन समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व विधानसभाध्यक्ष डॉक्टर सी पी जोशी , भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद चन्द्रप्रकाश जोशी, पूर्व सांसद रामचरण मोहरा, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, सिविल लाईंस विधायक गोपाल



शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंदचार्यजी आदि की भी गरिमामय उपस्थिति रहेगी। 5 सितम्बर को उद्घाटन की पूर्व संध्या पर विप्र बैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (विकी) की ओर से वंदन पर्व का आयोजन राजस्थान कन्वेंशन सेंटर में शाम 5 बजे से होगा। इसमें देश-प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति एवं व्यवसायी राजस्थान

के विकास तथा समाज के युवाओं के स्वावलंबन पर विचार मंथन करेंगे। इस आयोजन में राजस्थानी थीम की झलक होगी। साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा और ज्ञानपीठ निर्माण में सहयोग देने वाले उद्यमियों का सम्मान किया जाएगा। रात्रिभोज का भी आयोजन रहेगा। पार्किंग और विशाल हॉल,

ऑडिटोरियम।भूतल : सेमिनार हॉल, कार्यालय, अतिथि कक्ष और परशुराम मंदिर।प्रथम से तृतीय तल : सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु कार्यक्षेत्र।चतुर्थ-पंचम तल : प्रतियोगी परीक्षा कोशिका, वैदिक अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप इनक्यूबेशन और कौशल विकास केन्द्र।पंचम एवं षष्ठम तल : कन्या छात्रावास एवं मेस हॉल।छत: गायत्री, गीता, गौ, गंगा ग्रीनरी पर आधारित फाइट जी गार्डन होगा सबसे आकर्षण का केंद्र। साथ ही यज्ञशाला भी होगी।

यह रहेगी संचालन व्यवस्था : ज्ञानपीठ की गतिविधियों के संचालन के लिए 15 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें पूर्व पुलिस महानिदेशक ओमेश भारद्वाज चैयरमैन, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा कार्यकारी चैयरमैन और सतीश चंद्र शर्मा

सुविचार

साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को संभव बनाते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

जनता के लिए बहुत बड़ी राहत

केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। इससे महंगाई काबू में आएगी और लोगों की जिंदगी आसान होगी। देशवासी लंबे अरसे से यह उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कोई ऐसी घोषणा करे, जिससे आर्थिक मोर्चे पर हालात बेहतर हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से ‘अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार’ की घोषणा की थी। अब जीएसटी परिषद ने जिन सुधारों को मंजूरी दी है, वे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाएंगे। इसे दीपावली से पहले एक बड़ा उपहार समझना चाहिए। इन घोषणाओं को लागू करने से लोगों का जीवन खुशहाल होगा और ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनेगा। ये घोषणाएं मांग में वृद्धि करेंगी। शैंपू, हैयर ऑयल, टूथपेस्ट, दूधब्रश, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज आदि को 5 प्रतिशत स्लैब में लाने से लोगों को सुविधा होगी। सिलाई मशीन और उसके पुर्जों को इसी स्लैब में शामिल करने से सिलाई उद्योग को फायदा मिलेगा। सरकार ने नक्शों, चार्ट, ग्लोब, पेंटिल, शार्पनर, ड्रेजर, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक पर पूरी तरह छूट देकर शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार यूं तो किसानों के कल्याण के लिए समय-समय पर कई घोषणाएं करती रहती है। उसने जीएसटी दरों में जो बदलाव किया है, उसमें भी किसानों का ध्यान रखा है। ट्रैक्टर और उसके पुर्जों एवं टायरों को 5 प्रतिशत स्लैब में लाने का फैसला खेती पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करेगा। फसल बुआई और कटाई के दिनों में ट्रैक्टर पर खर्च बढ़ जाता है। कर दरों में बदलाव से किसान के लिए ट्रैक्टर खरीदना और उसका रखरखाव करना सस्ता हो जाएगा।

सीमेंट पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत करने से भवन निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। इससे घर बनाने का सपना भी पूरा होगा। सरकार ने 33 जीवनरक्षक दवाइयों पर जीएसटी को घटाकर शून्य कर दिया, जो सराहनीय है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाइयों पर जीएसटी शून्य होने से रोगियों और उनके परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। 350 सीसी या उससे कम सीसी वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से कम एवं मध्यम आय वाले परिवारों के लिए वाहन खरीदना आसान हो जाएगा। बस, ट्रक जैसे वाहनों पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत करने से इनके संचालन से जुड़े व्ययसयों को फायदा मिलेगा। यूएचटी दूध, पहले से पैक और लेबल वाले छेना या पनीर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने से आम परिवारों के लिए गुजारा करना आसान हो जाएगा। सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) से भी जीएसटी घटाने से करोड़ों परिवार हर महीने काफी राशि बचाने में समर्थ होंगे। जब सरती और सुलभ चीजें बाजार में मिलेंगी तो पोषण का स्तर बढ़ेगा। पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सांस, पास्ता, इस्टेट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स आदि पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करने से आम आदमी का खानपान और लजीज हो जाएगा। सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट देने से बीमा कवरेज को बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से तो जनता को काफी फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी सुधार धरातल पर दिखाई दें। ऐसा न हो कि कंपनियां खुद तो जीएसटी छूट ले लें और जनता पहले की तरह महंगाई की चक्की में पिसती रहे।

ट्वीटर टॉक

इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दो नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत – यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी-सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए।

—राहुल गांधी

अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से राजस्थान के उद्योग, रोजगार और छोटे व्यवसाय गहरे संकट में हैं। राज्य के प्रमुख उद्योग हैंड्रीकंपट, जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल और अन्य निर्यात आधारित क्षेत्र इस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं।

—सचिन पायलट

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को जो वादा किया था, उसके अनुरूप जीएसटी में जो बदलाव किए गये हैं, वह स्वागत योग्य है। इससे देशवासियों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार का यह कदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को दर्शाता है।

—वसुंधरा राजे

प्रेरक प्रसंग

सज़ा की तार्किकता

गृहयुद्ध के समय एक युवा सैनिक विलियम स्कॉट गश्त के दौरान थकान से बुर होकर सो गया। सैन्य अनुशासन के अनुसार इसकी सजा मौत थी। सैनिक अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जब यह खबर राष्ट्रपति लिंकन तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत मामले की फाइल मंगवाई। लिंकन ने अधिकारियों से पूछा, 'क्या यह सच है कि यह युवक लगातार दो रात गश्त पर रहा और तीसरी रात नींद से हार गया?' अधिकारी बोले, 'हां, सर।' लिंकन ने गहरी सांस ली और कहा, 'तो फिर दोष उसका नहीं, थकान का है। मैं नहीं मानता कि अमेरिका अपने ही बेटे को सिर्फ सो जाने की वजह से गोली से मार दे।' उन्होंने सजा को माफ कर दिया और सैनिक को वापस उसकी यूनिट में भेज दिया। कुछ महीनों बाद वही सैनिक एक युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ा और अपने साथियों की जान बचाई। युद्ध के बाद उसने कहा, 'अगर राष्ट्रपति ने उस दिन मुझे क्षमा न किया होता, तो आज यह बलिदान संभव न होता।'

सामयिक

भाषाई अभद्रता के चरम पर भारतीय राजनीति

संदीप सृजन

मोबाइल : 9406649733

भारतीय राजनीति का इतिहास विचारों की टकराहट, वैचारिक बहस और लोकतांत्रिक मूल्यों से समृद्ध रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक संवाद में भाषाई अभद्रता एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। नेताओं के बीच नीतियों और विकास पर चर्चा की जगह व्यक्तिगत हमले, अपशब्द, और जातिगत-लैंगिक अपमान बढ़ते जा रहे हैं। यह न केवल राजनीतिक संस्कृति को दूषित कर रहा है, बल्कि सामाजिक एकता को भी कमजोर कर रहा है। हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। भाषाई अभद्रता से तात्पर्य उन भाषणों और टिप्पणियों से है जो अपशब्दों, व्यक्तिगत हमलों, जातिगत-धार्मिक अपमानों, और लैंगिक टिप्पणियों से भरे होते हैं। यह भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और चौबीस घंटे न्यूज चैनलों के युग में यह चरम पर पहुंच गई है। पहले जहां नेताओं के बीच नीतिगत बहसें हुआ करती थीं, वहीं अब व्यक्तिगत हमले और अपशब्द सामान्य हो गए हैं।

बिहार के दरभंगा में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी, के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई। एक वायरल वीडियो में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हिंदी में अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुना गया। इस मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा, और तेजस्वी यादव के पोस्टर थे, हालांकि ये नेता उस समय मंच पर मौजूद नहीं थे। इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक रुख अपनाने का मौका दिया। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र पर धब्बा और महिला विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताते हुए कड़ी निंदा की। बीजेपी ने पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की और महिला विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताते हुए कड़ी निंदा की। बीजेपी ने पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की और महिला विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताते हुए कड़ी निंदा की। बीजेपी ने पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की और महिला विरोधी मानसिकता का उदाहरण बताते हुए कड़ी निंदा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ के उद्घाटन के दौरान इस घटना पर भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'हमारा संसार है, मां हमारा स्वाभिमान है। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, फिर उन्हें क्यों गाली दी गई? यह न केवल मेरी मां का अपमान है, बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि यह इस अपमान को माफ कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस ने इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया और कहा कि यह एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय युवा कांग्रेस नेता मोहम्मद नोशद ने माफी मांगी और कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि, बीजेपी ने इसे विपक्ष की संस्कृति विरोधी और महिला विरोधी मानसिकता का हिस्सा बताया। यह घटना अकेली नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही भाषाई अभद्रता के दोषी रहे हैं।

आजकल सोशल मीडिया ने नेताओं को वायरल होने की होड़ में अपशब्दों का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया है। ट्विटर और वायरल वीडियो तुरंत ध्यान खींचते हैं, जिससे नेताओं का ध्यान नीतिगत मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत हमलों पर चला जाता है। सत्ता और विपक्ष के बीच गहरा धुंधीकरण है। विपक्ष को चुसपैटिए या देशद्रोही और सत्ता को तानाशाह जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, जो वैमनस्य को बढ़ाते हैं। न्यूज चैनल और डिबेट शो भाषाई अभद्रता को बढ़ावा देते हैं। भाषाई अभद्रता के प्रभाव गहरे और दीर्घकालिक हैं। अपशब्द और व्यक्तिगत हमले समाज में जातिगत, धार्मिक और लैंगिक तनाव को बढ़ाते हैं। बिहार की घटना में, मां के खिलाफ टिप्पणी को हर मां का अपमान बताकर बीजेपी ने इसे सामाजिक मुद्दा बना दिया। राजनीतिक संवाद का स्तर गिरने से जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थानों पर कम होता है। लोग नेताओं को आदर्श के रूप में देखना बंद कर देते हैं। अधिकांश अपशब्द लैंगिक या जातिगत होते हैं, जिससे महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

अपशब्दों और अपमानजनक टिप्पणियों के

मुद्दा

समाज की बुराइयों से लड़ सके, वही सच्चा शिक्षक

नन्द किशोर अगवाल

मोबाइल : 9945395760

शिक्षक को समाज में माता-पिता समान इश्वर का रूप माना जाता है। शिक्षक व्याग, सम्पन्न और न्याय की वह मसाल है, जो स्वयं जलकर विद्यार्थियों को यश मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रकाशमान होती है। शिक्षक के कला-गुणों पर ही देश का उज्ज्वल भविष्य तैयार होता है, और यही है सच्चे शिक्षक की पहचान। 5 सितंबर 1888 को एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मे डॉ. राधाकृष्णन ने अपने जीवन

काल के 40 वर्ष एक आदर्श शिक्षक के रूप में समर्पित कर दिए। 1962 से, जब वे देश के राष्ट्रपति बने, तब से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनके जन्मदिन पर देश में 'शिक्षक दिवस' मनाया जाता है।

ऐसे अनगिनत महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने देश की जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर देश व समाज की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ निछावर कर दिया, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र भी प्रमुख है। देश में महिला शिक्षा की पहली लौ जलाने वाली महान समाज सुधारक सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले थी, जिन्होंने महिला शिक्षा को सफल बनाने के लिए कई कठिनाइयों से संघर्ष किया, साथ ही उन्हें



भयंकर सामाजिक विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोग उन पर कीचड़, पत्थर, गोबर फेंकते थे, मारते थे, गालियां देते थे, श्राप देते थे, तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखते थे। इतने असहनीय अत्याचारों के बावजूद उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले की मदद से लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। नारी शक्ति संदेव उनकी ऋणी रहेगी। सोचिए जरा आज समाज में कितने शिक्षक हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. राधाकृष्णन जैसा संघर्ष करके समाज में फैली बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं और आदर्श पीढ़ी के शिक्षक कहलाने के काबिल हैं।

नजरिया

शिक्षक ज्ञानवान ही नहीं, चस्त्रिवान पीढ़ी का निर्माण करें

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

शिक्षक ही सभ्यता और संस्कृति के असली शिल्पी होते हैं। विज्ञान, तकनीक और राजनीति चाहे जितनी प्रगति कर लें, यदि शिक्षा और शिक्षक दिशा न दें तो मानवता दिशाहीन हो जाती है। इसी कारण 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा आरंभ हुई। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को होता है, जो भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज में शिक्षक के महत्व, उनके योगदान और मार्गदर्शक भूमिका को सम्मान देना है। यह अवसर विद्यार्थियों और समाज को याद दिलाता है कि शिक्षक केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं बल्कि आदर्श, प्रेरक और चरित्र-निर्माता भी होते हैं। आज जबकि नया भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत निर्मित हो रहा है, तब शिक्षकों की भूमिका अधिक प्रासंगिक हो गयी है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के तिरुत्तनी में हुआ था। वे एक महान दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दर्शनशास्त्र पढ़ाया। उनकी पुस्तकें 'इंडियन फिलोसॉफी' 'दी हिन्दू यूथ ऑफ लाइफ' और 'दी आइडलिट ऑफ लाइफ' विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुईं। वे 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ शिष्यों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उन्होंने विनम्रता से कहा कि यदि आप लोग मेरे जन्मदिन को विशेष रूप से मनाना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से ही 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉ. राधाकृष्णन का संदेश यही था कि शिक्षक समाज की रीढ़ हैं और उनका सम्मान करना ही वास्तविक राष्ट्र निर्माण है। निश्चित ही शिक्षकों का यह सम्मान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य का घोषणापत्र है।

यह दिवस राष्ट्र को शिक्षा, विज्ञान, शांति एवं प्रगति का सन्देश देने के लिए कृत संकल्पित है। भारत का इतिहास शिक्षा की गौरवमयी परंपरा से जुड़ा है। प्राचीन समय से भारत शिक्षा का बड़ा केन्द्र रहा है और उसने संसार में जगतगुरु की भूमिका निभाई है। नालंदा और तक्षशिला जैसे



विश्वविद्यालयों ने भारत को जगतगुरु का दर्जा दिलाया। महान दार्शनिक आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा था-व्यक्तित्व-निर्माण का कार्य अत्यन्त कठिन है और यह केवल निःस्वार्थी एवं जागरूक शिक्षक ही कर सकता है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। प्राचीन भारतीय दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य सा विद्या या विमुक्तये' रहा है, अर्थात् शिक्षा वही है जो मुक्ति दिलाए। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह 'सा विद्या या निमुक्तये' बन गई है अर्थात् शिक्षा वही है जो नौकरी दिलाए। यही कारण है कि स्कूलों में विद्यालयों की संख्या बढ़ने के बावजूद समाज में अपराध और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं।

महात्मा गांधी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है-एक स्कूल खुलेगा तो सो जेलें बंद होंगी। परन्तु आज स्थिति इसके विपरीत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने इस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया है। इसमें केवल क्या पढ़ना है पर ही नहीं, बल्कि कैसे पढ़ना है, इस पर भी जोर दिया गया है। आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, उद्यमशीलता और नैतिकता को शिक्षा के केंद्र में रखा गया है। लेकिन इन सभी का केन्द्रबिंदु शिक्षक ही है। यदि शिक्षक प्रेरणाहीन, निरुत्साहित या असंवेदनशील होंगे तो कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। शिक्षा केवल किताबों और पाठ्यक्रम से नहीं, बल्कि शिक्षक की जीवंत उपस्थिति से सार्थक होती है। पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉ. एंपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था-अगर कोई देश भ्रष्टाचार मुक्त है और सुंदर दिमागों का राष्ट्र बन गया है, तो उसके लिए तीन प्रमुख व्यक्ति जिम्मेदार होंगे-पिता, माता और शिक्षक। यह कथन शिक्षा के महत्व को

सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करता है। भारत अमूलकाल की ओर बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का स्वप्न तभी साकार होगा जब हमारे शिक्षक नई पीढ़ी को केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि चरित्रवान भी बनाएं।

राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। नेल्सन मंडेला ने कहा था-शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे दुनिया बदली जा सकती है। युद्ध और आतंक के बीच मानव मस्तिष्क में जन्म लेते हैं, इसलिए बचपन से ही शक्ति और सह-अस्तित्व के बीज बोने होंगे। बाबों को अपने देश से प्रेम के विषय-प्रेम यानी मानवता का पाठ सिखाना होगा, तभी दुनिया से युद्ध, हिंसा, आतंक का खाल्ता होगा। भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुम्बक मूल मंत्र इसमें सहायक बन सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का स्वरूप धीरे-धीरे मिशन से व्यवसाय की ओर झुकता जा रहा है। ज्ञान की बोली लग रही है, शिक्षक और छात्र के संबंधों में अविश्वास और हिंसा की खबरें बढ़ रही हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण रोकने और उसे मानवीय मूल्यों से जोड़ने की जिम्मेदारी सबसे पहले शिक्षकों पर ही आती है। आज आवश्यकता केवल शिक्षा क्रांति की नहीं, बल्कि शिक्षक क्रांति की भी है। अच्छे पाठ्यक्रम, नई तकनीक और आधुनिक संस्थानों की व्यवस्था तभी सार्थक है जब उनके केंद्र में ऐसे शिक्षक हों, जो छात्रों को प्रेरणा दें, जो उनके सर्वांगीण विकास का माध्यम बनें। खेत, बीज और उपकरण के रहते हुए किसान न हो तो सब बेकार हैं। उसी प्रकार, विद्यालय, पाठ्यक्रम और तकनीक के रहते हुए यदि शिक्षक नहीं हैं तो सब निरर्थक है। शिक्षा विवेकानंद ने भी कहा था-सर्वांगीण विकास

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company/6/4 , 1st floor, Contentment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. Editor-Shreekanth Parashar. ("Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पातों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तराद्वी नहीं बना सकता। — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

